भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3986

उत्तर देने की तारीख 12 अगस्त, 2026 (बुधवार)

21 श्रावण, 1948 (शक)

प्रश्न

बोडोलैंड में परियोजनाएं

†3986. **श्री जयन्त बसुमतारीः**

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में विकास के लिए स्वीकृत कई परियोजनाएं अज्ञात कारणों से अभी भी अधूरी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के लिए स्वीकृत केंद्र प्रायोजित विकास परियोजनाओं और उनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो स्वीकृत की गई थीं लेकिन जिनके लिए अभी तक निधि आवंटित नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, भारत सरकार, असम सरकार तथा संबंधित बोडो समूहों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओएस) के अनुसार बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) के लिए विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) कार्यान्वित कर रहा है।

भारत सरकार, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स (बीएलटी) के बीच दिनांक 10.02.2003 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, सरकार ने तीन वर्ष की अवधि लिए 500 करोड़ रुपये का एक विशेष विकास पैकेज अनुमोदित किया था। इसके बाद, अगस्त 2008 में 250 करोड़ रुपये का एक अतिरिक्त पैकेज अनुमोदित किया गया। इन पैकेजों के तहत, 749.65 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 65 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, जिनमें से 741.65 करोड़ रुपये की लागत वाली 64 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार, असम सरकार और बोडो समूहों (एबीएसयू और एनडीएफबी समूहों) के बीच दिनांक 27.01.2020 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, सरकार ने तीन वर्षों की अवधि के लिए 750 करोड़ रुपये के विशेष विकास पैकेज को अनुमोदित किया है। इस पैकेज के तहत, 512.46 करोड़ रुपये की लागत वाली 13 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

*****